मजदूरी समय-समय पर निर्धारित की जाए जो भारत सरकार ने 1992 में कर दिया है। विभिन्न राज्य सरकारों के 1175 ऐसे मजदूरों की इकाई है। जिनके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए। अन्तर है विभिन्न राज्यों में यह सही है और इसके संबंध में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने का प्रस्ताव हुआ है। इस पर अमल नहीं किया गया है, लेकिन समय-समय पर विचार किया जा रहा है कि क्या यह संभव है कि सारे देश में एक मजदूरी निर्धारित कर दी जाए। यह विचाराधीन है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, please. Please be brief.

SHRI JIBON ROY: Sir, the Labour Ministers' Conference held in July, 1990 had recommended that the Minimum Wages Act should be put in the Ninth Schedule of the Constitution. I would like to know whether the Government of India is thinking of implementing it.

डा. जगन्नाथ मिश्र : महोदय, इस बात की सूचना तो नहीं है कि कानूनी वैधता को कहीं चुनौती दी गई है। अगर कानूनी वैधता में संवैधानिक आड़ में कुछ कहा जा रहा होगा किसी राज्य में तो उस पर सरकार विचार कर सकती है।

SHRIMATI MIRA DAS: Sir, it is the duty of the Government to raise the standard of living of the people of the country. But the National Sample Survey says that the minimum consumption requirement is Rs. 6,534/- in the case of rural areas and Rs. 7,542/- in the case of urban areas. It is from the report of the Minister. But here the Planning Commission says that the monthly income of a family in the rural areas is Rs. 181. Then, how can you say that a family with a monthly income of Rs. 181 as being above the poverty line? How has the Planning Commission estimated in this way? I know that the reply will not come.

MR. CHAIRMAN: You have the last word! Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बेल (बी.ई.एल.) में कुप्रबंध

*65. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जून, 1995 के "राष्ट्रीय सहारा" में "घोटालों एवं "राष्ट्रीय सहारा" में "घोटालों एंव अनियमितताओं में जकड़ा बेल-रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता पर सवालियां निशान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुप्रबंध के कारण संस्थान का बजट घाटा लगातार बढ़ने के कारण इसके कर्मचारियों में व्यापक असंतोष है, और

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त तथ्यों की जांच-पड़ताल की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत इलेक्ट्रनिक्स लिमिटेड द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार इस कम्पनी की गाजियाबाद यूनिट का घाटा जोकि 1993-94 में 6.11 करोड़ रूपए था वह 1994-95 में बढ़कर 10.07 करोड़ रुपए हो गया। इसका मुख्य कारण आर्डरों की कमी होना और बाद के वर्ष में वेतन संशोधन के कारण इस यूनिट द्वारा बकाया राशि की अदायगी किया जाना था। यह घाटा प्रबंध व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी के कारण नहीं हुआ जिससे यूनिट की कुल बिक्री बढ़ेगी और इसका वाणिज्यिक कार्यनिष्पादन बेहतर होगा।

(ग) इस समाचार रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य बातों की भी जांच की गई है। उक्त कथित अनियमितताएं निराधार पाई गई है।

Losses Incurred by HMT

*66. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: PH. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the overall losses of HMT during each of the last four years;

(b) which of the units of HMT are